गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपकरणों की खरीददारी

251. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड ने बी० एच०ई० एल० से किस-किस प्रकार के उपकरण खरीदे थे तथा इस संबंध में बोर्ड की तरफ अभी कितना राशि बकाया है; और

(ख) सिक्का और बांधर विद्युत केन्द्रों द्वारा कित-कित तारीख को कितनी-कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किये जाने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

एच० बी० जे० पाइपलाइन द्वारा गैस की सप्लाई

252. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों को एच० बी० जे० पाइप लाइन से गैस प्राप्त होगी तथा प्रत्येक को कितनी-कितनी मात्रा में गैस दी जाएगी ;

(ख) क्या उन क्षेत्रों को प्रस्तावित गैस की सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना है जो गुजरात में उन स्थानों के 25 किलोमीटर दूरी के भीतर पड़ते हैं जहां से पाइप लाइन गुजरती है; और

(ग) क्या ऐसी कोई मांग की गई है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) निम्नलिखित छः उर्वरक संयंत्रों तथा तीन बिजली घरों को गैस सप्लाई की जाएगी :--

1. **गुजरात**: फाल बैक के आधार पर एक बिजली घर को 2 एम एम सी एम डी की दर से गैस सप्लाई की जाएगी ।

2. **राजस्थान** : एक बिजली घर और एक उर्वरक संयंत्र को 3.25 एम एम सी एम डी की दर से जैसे देने का वचन दिया गया है ।

3. **मध्य प्रदेश** : एक उर्वरक संयंत्र के लिए 1.5 एम एम सी एम डी गैस देने का वचन दिया गया है ।

4. **उत्तर प्रदेश** : चार उर्वरक संयंत्रों तथा एक बिजली घर को कुल 8.25 एम एम सी एम डी की दर से गैस देने का वचन दिया गया है ।

(ख) और (ग) एच बी जे पाइपलाइन के साथ गैस के फालबैक उपभोक्ताओं को खोजने के लिए गैल कार्रवाई कर रही है ।

गैस निगम की स्थापना

253. **श्री मीर्जा इर्शाद बेग** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस का उत्पादन करने वाले गुजरात तथा असम राज्यों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सहयोग से गैस निगम की स्थापना करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक-गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भोपाल गैस दुर्घटना सम्बन्धी मामलों में सरकार द्वारा लगाये गये वकील

254. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन कार्बाइड, भोपाल के विरुद्ध भोपाल के न्यायालयों में चल रहे मामलों के संबंध में सरकार ने कितने वकीलों की सेवायें ले रखी हैं; और

(ख) अभी तक उन वकीलों को मुकदमों की फीस के रूप में कितनी धन राशि अदा की जा चुकी है तथा अभी कितनी धनराशि की अदायगी शेष है ?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) मैं० राबिन्स, जैले, लारसन एण्ड कपलान (सालिसीटरों की अमरीकी फर्म) जो पहले ही इस मामले में मुकदमें में लगी हुई है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में चल रहा मुकदमा भी शामिल है, के अतिरिक्त सरकार ने अब तक महान्यावादी के नेतृत्व में 7 न्यायवादियों के एक दल की नियुक्ति की है ।

भारतीय न्यायवादियों को रिटेनर शुल्क के रूप में फरवरी 1987 के अंत तक 45,000 रु० का भुगतान किया जा चुका है और इस संबंध में लगभग 35,000 रु० के बिलों को तय करना शेष रहता है । सरकार ने अमरीकी न्यायवादियों को फीस के रूप में अब तक 1.5 मिलियन डालर का भुगतान किया है और उनसे प्राप्त लगभग 1.7 मिलियन डालर के बिल अभी तय किये जाने बाकी हैं ।

Formation of a consortium of British firms

255. SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether India and U.K. have agreed in principle to form a consortuim of British firms led by the British Coal, a nationalised concern, to develop the Ghusick coal mine in West Bengal; if so, what are the details thereof; and

(b) whether International tenders would be issued for the turnkey project; if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): (a) The implementation of Ghusick Project of Eastern Coalfields Limited, with assistance from United Kingdom, was discussed in the meeting of the Indo-U.K. Joint Steering Group on Coal held in New Delhi on 10-11 February, 1987. It was agreed that the project would be undertaken on a turnkey basis for which BMCL would form a joint company with Trafalgar House who have been nominated by the British Coal as BMCL's collaborators. BMCL would have majority of shares in this joint company. It was also agreed that the CIL and the said joint company would enter into a suitable contract to perform the job. The British side had also confirmed in the meeting that offshore costs and the consultancy services costs for the projects would be met by a grant which could be of the order of upto £53 million. Preliminary discussions between the intended contractual parties have not been finalised so far.

(b) In view of the decision taken in the meeting of the Indo-U.K. Joint Steering Group on Coal held in New Delhi on 10-11 February, 1987, issue of international tenders